(ग) संसद सदस्यों के कोटे के लिए निर्धारित धनराशि कब तक जिला कलेक्टरों को भेज दी जायेगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमैंग): (क) लोकसभा के सभी सदस्यों (लोकसभा में नामित दो संसद सदस्यों को छोड़कर) को संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रति सांसद 50 लाख रू० की प्रथम किस्त को पहले ही जारी कर दिया गया है। राज्य सभा के उन 22 सांसदों जिन्होंने अपने विकल्प दिए थे, के बारे में भी धनराशि जारी की जा चुकी है। राज्य सभा के 74 सांसदों जिनके विकल्प जुलाई, 95 मास के अन्त तक प्राप्त हुए थे, को धनराशि शीघ्र ही जारी की जा रही है।

(ख) चूंकि राज्य सभा के कुछ सांसदों ने अपने विकल्प नहीं दिए हैं अतः वर्ष 1995-96 के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत उनसे सम्बद्ध धनराशि को जारी करने का कार्य पूरा नहीं किया गया है।

(ग) राज्य सभा सांसदों से वर्ष 1995-96 के लिए उनके विकल्प प्राप्त होने पर ही धनराशि को जारी किया जा सकता है।

Cooperative sector in Sugar Production

773. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for providing assistance to Cooperative Sector for sugar production;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the specific steps proposed to encourage the cooperative sector to enter the sugar sector?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) As per the licensing policy guidelines announced by the Government of India vide Press Note No. 16 (1991) series dated 8.11.91, other things being equal preference in licensing is to be given to proposals from the cooperative sector over the public and private sector.

Assistance is also provided for cane development and modernisation.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यातकों को चावल की आपूर्ति किए जाने में विलम्ब

774. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:**
श्री जनेश्वर मिश्र:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल निर्यातकों को चावल की आपूर्ति में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने किन बंदरगाहों पर चावल के निर्यात की व्यवस्था की है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम निजी निर्यातकों के माध्यम से चावल की आपूर्ति किए जाने का आग्रह करता रहा है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम की ओर से अपनी खुले बाजार की बिक्री की योजना के अधीन निर्यात के प्रयोजन के लिए चावल के प्रत्याशित खरीदारों को चावल रिलीज करने में किसी प्रकार विलम्ब नहीं हुआ है। तथापि, जहां पर रेल-संचलन होता है वहां पर कुछ विलम्ब हुआ है। यह विलम्ब स्टाक के संचलन हेतु उन स्टेशनों पर रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण हुआ है जहां क्रेताओं द्वारा चावल का निरीक्षण किया गया है और इसे स्वीकार किया गया है। इसके अलावा उनके द्वारा वांछित स्थानों पर भी विलम्ब हुआ है।

(ख) चूंकि फिलहाल, भारतीय खाद्य निगम चावल का सीधे निर्यात नहीं कर रही है इसलिए इसे पत्तनों पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी है।

(ग) जी, नहीं।

गरीबी में बढ़ोतरी

775. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "पावर्टी राइजिंग बाई टू परसेन्ट इनुअली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर मिलाया गया है;

434-405-E3A

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गत वर्षों के दौरान देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले व्यक्तियों की संख्या में 2 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई और

(ग) क्या यह सच है कि 40.1 प्रतिशत वर्तमान आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी अनुमानों के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में 1983-84 में 271.0 मिलियन से घटकर 1987-88 में 237.7 मिलियन होने पर 3.1 प्रतिशत वार्षिक की कमी आई थी। योजना आयोग द्वारा गठित गरीबों के अनुपात तथा संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल के अनुमानों के अनुसार संख्या 1983 में 327.0 मिलियन से घटकर 1987-88 में 312.7 मिलियन होने पर 1.1 प्रतिशत वार्षिक की कमी आई थी।

सरकारी अनुमानों के अनुसार 1987-88 में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का प्रतिशत 29.9 था। विशेषज्ञ दल ने इसका अनुमान 39.3 प्रतिशत लगाया है।

बाद के वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

Retail Prices of Essential Commodities

776. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the retail prices of essential commodities like wheat, rice, sugar, edible oils, pulses, tea etc. during the last three years;

(b) the reasons for increase in prices; and

(c) the steps taken by Government to control prices of essential commodities?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH) (a) Month-end retail prices of selected essential commodities for the last 3 years ending July, 1995 are given in the Statement (*See* below).

(b)and (c) Rise in the price levels of commodities is the result of an interplay of various factors operating on the demand and supply sides of the economy. The gap between the demand and supply of commodities like pulses and edible oils, decline in production of a particular commodity during the year, revision in the Minimum Support Prices of agricultural products warranted by rise in input costs, increased demand due to continuous rise in population over the years are some of the reasons for rise in the prices. Among the measures taken by the Government to contain the prices include the incentives given to farmers and manul facturers to enhance their output, import of edible oils, pulses, sugar, cotton whenever necessary, strict action against hoarders and black marketeers under Essential Commodities Act, 1955 and Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980. The essential commodities are also being supplied at reasonable prices through cooperatives stores and State Civil Supplies Corporations in addition to those supplied through the Public Distribution System and Revamped Public Distribution System. State Governments have been requested to keep a close watch on the prices of essential commodities in their States/UTs.